THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that as on 30th June, 1993 there were 3563 currency chests maintained by various banks of RBI's behalf.

(b) The volume of amount held by these currency chests as on 30th June, 1993 was Rs. 36811.65 crores.

Proposal of Rupert Murdoch for Opening Up of the skies

*92. DR. NAUNIHAL SINGH: SHRI G.G. SWELL:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal of Rupert Murdoch for opening up of the skies;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that such an action will constitute a media invasion since this will have a serious impact on the cultural outlook of our people; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

केन्द्र सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया कर्जे

*93. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गैर-विकासात्मक व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई ऋणों की राशि एवं देश में मुद्रा परिचालन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो दिसम्बर, 1992 तथा दिसम्बर, 1993 में क्रमशः केन्द्र सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त कितनी-कितनी ऋण राशि बकाया थी और कितनी-कितनी मुद्रा परिचालन में थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुद्रा परिचालन में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रुपए की क्रय शक्ति में और कमी आई है; और

(घ) 1982 की कीमतों के आधार पर दिसम्बर, 1992 तथा दिसम्बर, 1993 के दौरान भारतीय रुपए की क्रय शक्ति के संबंध में आकलन क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) सरकार के कुल ऋण मांगों में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए कर्जे एक हिस्सा हैं। सरकार की ऋण मांगें कुल व्यय (विकासात्मक और गैर-विकासात्मक) तथा कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के आधार पर निर्भर है। तदनुसार इसका गैर-विकासात्मक व्यय जैसे व्यय के एक घटक से सीधा संबंध नहीं है और यह भारतीय रिजर्व बैंक से ऋणों के नाम से एक प्रकार के सरकारी ऋण हैं।

सरकार के राजकोषीय घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार दोनों में रिजर्व मुद्रा देयता के बढ़ जाने के कारण मुद्रापूर्ति (एम०-3) में वृद्धि हुई है।

(ख) केन्द्र सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया निवल कर्जे (एम०आर०सी०सी०जी०) और 25 दिसम्बर, 1992 एवं 24 दिसम्बर, 1993 को मुद्रा पूर्ति (एम-3) इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

	25 दिसम्बर, 1992	24 दिसम्बर, 1993
(i) एन०आर०सी०सी०जी०	93716	104760
(ii) एम-3	353949	408413

(ग) भारतीय रुपए की क्रय शक्ति का मूल्यांकन औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) के परिचालन द्वारा मुद्रास्फीति दरों के घटबढ़ के आकलन के आधार पर किया गया। सी०पी०आई० के बढ़ने के बावजूद इसमें कमी आई है। उपभोक्ता कीमतें मुद्रा पूर्ति, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं।

(घ) औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=100) के अनुसार भारतीय रुपए की क्रय शक्ति का आकलन दिसम्बर, 1992 के 41.15 पैसे के मुकाबले दिसम्बर, 1993 में 37.38 पैसे था।

Strike by Bank Employees

*94. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI SURESH PACHOURI:

will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times dated the 18th February, 1994 captioned "Bank Staff strike near total" all over the country, on 17th February 1994 including RBI and reported statement of the General Secretary of Bank Employees Federation of India saying that the strike was a warning to Government that the ill-conceived policies at the dictates of IMF and World Bank will not be tolerated by bankmen and the country's people;

(b) what were the main demands, reasons which led to strike and suspension of clearing house operations in the country;

(c) what steps Government propose to take to meet their demands, particularly immediate holding of meaningful wage negotiations, as the last charter was valid only upto November, 1992; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The one-day strike on 17.2.94 in some of the banks was to protest primarily against alleged privatisation of banks, closure of branches, job security, early wage revision, and introduction in Parliament of the Bill enabling nationalised banks to raise share capital from the public. Government have, on a number of occasions, allayed the fears of bankmen and have reiterated there was no intention to denationalise public sector banks or to undertake any retrenchment of staff. At the same time, it has been emphasised that there is an urgent need to improve efficiency so as to meet the requirements of a competitive economy.

In relation to the demand for wage revision, several rounds of discussions on the charter of demands submitted by the employees' unions for the 6th Bipartite Settlement have so far taken place between IBA and representatives of employees' unions and in pursuance of these discussions, memoranda of understanding have already been signed between the major employees unions and the IBA with regard to pension in lieu of CPF and on computerisation and mechanisation. Further discussions between IBA and the employees' representatives are going on.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदे

*95. श्री सुन्दर सिंह भंडारी:
श्री ओ० राजगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदों में कमीशन के लिए जाने को वैधता प्रदान की है;

(ख) क्या इन नियमों में विगत सात वर्षों में कोई अपवाद भी रहे हैं; और

(ग) विवादास्पद सौदे के मामले में उससे निपटने के लिए क्या कोई पंचाट व्यवस्था उपलब्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कुल्लू-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल फाइबर का बिछाया जाना

*96. श्री महेश्वर सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: